

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2009/फाल्गुन 15, 1930

No. 102]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2009/PHALGUNA 15, 1930

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयोग का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

सं. 1/55/2000-डीसीएचएल/समन्वय/एआईएचबी.—
भारत सरकार के संकल्प संख्या 1/55/2000-डीसीएचएल/
समन्वय/एआईएचबी, दिनांक 30 जुलाई, 2008, 27 अगस्त, 2008,
2 सितम्बर, 2008, 11 सितम्बर, 2008, 16 सितम्बर, 2008,
23 सितम्बर, 2008, 21 अक्टूबर, 2008, 4 नवम्बर, 2008,
26 नवम्बर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008, 10 दिसम्बर, 2008,
26 दिसम्बर, 2008, 2 जनवरी, 2009, 19 जनवरी, 2009,
23 जनवरी, 2009, 29 जनवरी, 2009, 4 फरवरी, 2009 और
19 फरवरी, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित
व्यक्तियों को अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य
के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है :

1. श्री राजा विपिन जैन,
4569, गली नाथन सिंह,
पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006
2. श्री अमित हरीभाई चौधुरी,
20, मणिचंद्रा सोसाइटी,
नजदीक सुरधारा सर्कल,
मामनगर, अहमदाबाद-52

बोर्ड के उपर्युक्त सदस्य हथकरघा क्षेत्र के लिए समग्र विकास
कार्यक्रम बनाने में सरकार को सलाह देकर उपर्युक्त सदस्य की
पदाधि बोर्ड की समग्रता के अन्तर्गत मार्च 30, 2008 से
दो वर्ष की होगी।

यह बोर्ड हथकरघा क्षेत्र के समाज-आर्थिक, सांस्कृतिक और
कलात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के समग्र विकास
कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को सलाह देगा। यह बोर्ड विशेष रूप
से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सलाह देगा :—

- (i) देश की कपड़े की आवश्यकता को अधिकाधिक
हथकरघा क्षेत्र से पूरा करना।
- (ii) बुनकरों में बेरोजगार और अल्परोजगार को कम करने
और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के
लिए हथकरघा क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाना।
- (iii) हथकरघा की शिल्प परम्परा को बनाए रखना और
इसमें अधिक सुधार करना।
- (iv) देश और विदेशों में हथकरघा वस्त्रों के विपणन में
वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाना।
- (v) इस क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शक्ति
क्षेत्रों के विकासात्मक प्रयत्नों में समन्वय स्थापित
करने के लिए कदम उठाना।
- (vi) समय-समय पर इस उद्योग के विकास में हुई प्रगति
की समीक्षा करना।

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं
विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES**(Office of the Development Commissioner
for Handlooms)****RESOLUTION**

New Delhi, the 26th February, 2009

No. 1/55/2000-DCHL/Coordn/AIHB.—In partial modification of Government of India's Resolution No. 1/55/2000 DCHL/Coordn/AIHB, dated 30th July, 2008, 27th August, 2008, 2nd September, 2008, 11th September, 2008, 16th September, 2008, 23rd September, 2008, 21st October, 2008, 4th November, 2008, 26th November, 2008, 1st December, 2008, 10th December, 2008, 26th December, 2008, 2nd January, 2009, 19th January, 2009, 23rd January, 2009, 29th January, 2009, 4th February, 2009 and 19th February, 2009, the following persons have been appointed as Non-Official Members in the All India Handloom Board with immediate effect :

1. Shri Raja Vipin Jain,
4569, Gali Nathan Singh,
Pahari Dhiraj,
Delhi-110006
2. Shri Amit Haribhai Chaudhary,
20, Manichandra Society,
Near Surdhara Circle,
Mamnagar, Ahmedabad-52

The above newly appointed Members of the Board would advise the Government in the formulation of overall development programme in the Handloom Sector. The term

of Office of the above Members will be concurrent with the term of the Board i.e. a period of two years from 30th July, 2008.

The Board will advise the Government in the formulation of the overall development programme in the handloom sector keeping in view socio-economic, cultural and artistic perspective. In particular, the Board will advise the Government regarding achievement of the following objectives :—

- (i) to meet the clothing needs of the country progressively from the handloom sector;
- (ii) to make handlooms an effective instrument of reducing unemployment and under-employment and achieving higher standard of living for weavers;
- (iii) to preserve and further promote the craft heritage of our handlooms;
- (iv) to devise strategies for expanding markets for handlooms within the country and abroad;
- (v) to take steps for effective coordination of the developmental efforts of the various State Governments/Union Territories in this sector; and
- (vi) to review the progress of development from time to time.

B. K. SINHA Jt. Secy.
& Development Commissioner